संपादकीय

कार्रवाईयां मजबूत, साक्ष्य कमजोर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में लोकसभा में जानकारी दी कि ईडी ने पिछले दस साल में धनशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कुल पांच हजार दो सौ सत्तानबे मामले दर्ज किए, लेकिन इनमें से सिर्फ चालीस आरोपों में ही दोष सिद्ध हो सका। इस जवाब से सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में दर्ज होने वाले मामलों की बुनियाद में सबूतों का आधार कितना ठोस था और किन वजहों से प्रवर्तन निदेशालय पर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर कार्रवाई करने के आरोप लगते हैं! दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से धनशोधन के आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआइ की ओर से छापे या गिरफ्तारियों के मामले सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे कई मामलों में होने वाली कार्रवाइयों की जैसी प्रकृति देखी गई, उसमें अब ईडी को विपक्ष की आवाज को दबाने का औजार बनाए जाने के आरोप भी लगने लगे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी प्रवर्तन निदेशालय को एहतियात बरतने या हिदायत देने की कोशिश हो चुकी है। मगर आरोपों में साक्ष्यों को लेकर शायद गंभीरता नहीं आ पाई है या फिर इसमें एक परिपक्व दृष्टि का अभाव दिखता है। शायद यही वजह है कि बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामलों में दोषसिद्धि की बहुत कम दर का हवाला देते हुए ईडी से अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। जाहिर है कि कुछ समय से धनशोधन के आरोपों में छापा या फिर गिरफ्तारी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, मगर उनमें से बहुत कम मामलों में आरोप साबित हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दोषसिद्धि की दर को बड़ाने के लिए वैज्ञानिक जांच करने की सलाह दी। पहले भी धनशोधन के आरोप पर होने वाली कार्रवाइयों को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और बिना मजबूत साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी के मामलों की विश्वसनीयता कसौटी पर रही है। इसके बावजूद लगातार इस तरह के आरोप में छापे या गिरफ्तारी के मामले सामने आए। हकीकत यह है कि धनशोधन के मामले में गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप के साथ ईडी ने कार्रवाई में जितनी हड़बड़ी दिखाई, उतनी ही शिद्दत से आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश नहीं किए। नतीजतन, ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर काफी कम रही। अंदाजा इससे लग सकता है कि शीर्ष अदालत को यह कहने की जरूरत पड़ी कि जिन मामलों में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, प्रवर्तन निदेशालय को उन्हें अदालत में साबित करने की जरूरत है। अदालत की यह टिप्पणी यही दर्शाती है कि जिस तेजी से धनशोधन के मामलों में ईडी ने कार्रवाई किए, उसे साबित करने को लेकर उसके भीतर कोई गंभीरता नहीं दिखी। तो क्या वजहें हैंड़ आखिर क्या कारण है कि विपक्षी दलों को प्रवर्तन निदेशालय की मंशा पर और उसके सरकार के इशारे पर काम करने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाने का मौका मिलता हैड़ गैरकानूनी धनशोधन के मामलों की जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अगर दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर बेहद कम है तो क्या यह प्रवर्तन निदेशालय की साक्ष्यों को लेकर गंभीरता में कमी का सूचक नहीं है? ईडी जैसी सरकारी एजेंसी की विश्वसनीयता उसकी कार्रवाइयों की बुनियाद और उसमें दोषसिद्धि की दर के आधार पर ही बनती या बिगड़ती है, यह बात सबसे ज्यादा तो ईडी के ही ध्यान में होनी चाहिये।

सचेत आदमी सीखना मरते दम तक नहीं छोड़ता। जो सीखने की उम्र में ही सीखना छोड़ देते हैं, वे मूर्खता और अहंकार के दयनीय जानवर हो जाते हैं।

– हरिशंकर परसाई

आज का इतिहास

- 1270 येकुनो अमलाक ने आखिरी ज़गवे राजा को पदच्युत कर दिया और 700 से अधिक वर्षों तक चलने वाले शासनकाल की शुरुआत करते हुए इथियोपिया के सिम्पीरियल सिंहासन को जब्त कर लिया।
- 1500 पुर्तगाली समुद्र जहाज के कैप्टन डियागो डियाज मैडागास्कर को देखने वाले पहले यूरोपीय बने।
- 1512 कंबराई-इंग्लैंड की लीग का युद्ध और सेंट-मैथ्यू की लड़ाई में लगे एक संयुक्त फ्रेंको-ब्रेटन बेड़े, नौसेना के सबसे शक्तिशाली जहाज को नष्ट कर दिया।
- 1628 स्वीडिश युद्धपोत वासा ने स्टॉकहोम से नौसैनिक यात्रा में एक समुद्री मील से भी कम समय में तीस साल के युद्ध में लड़ने के लिए डूब जाने के बाद डूब गया।
- 1755 अंग्रेजों द्वारा वर्तमान कनाडाई समुद्री प्रांतों से एकेडियन के निष्कासन की पहली लहर की शुरुआत चिग्नटेको में बे ऑफ फनी अभियान के साथ हुई।
- 1755 अकादमी का निष्कासन फंड़ी अभियान की खाड़ी के साथ शुरू किया गया।
- 1759 कर्लोस तृतीय स्पेन का सम्राट बना।
- 1759 कार्लोस स्पेन का राजा बना।
- 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले दस्तावेज की प्रति औपचारिक रूप से लंदन पहुंचे।
- 1793 लौवर आधिकारिक तौर पर पेरिस, फ्रांस में खोला गया।
- 1793 लौवर आधिकारिक रूप से 537 चित्रों की प्रदर्शनी के साथ पेरिस में खोला गया।

कविता

हवा का ज़ोर वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना
कहीं गरजन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना

उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना
ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना

ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे
जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे

जो भूखा रहकर, धरती चीरकर जग को खिलाता है
जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिलमिलाता है

–भवानी प्रसाद मिश्र

केदारनाथ आपदा: पर्यावरणविदों के सुझावों की अनदेखी से उपजा संकट

■ जयसिंह रावत

वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा के 11 साल बाद 31 जुलाई की रात एक बार फिर केदार घाटी में जलप्रलय जैसा माहौल पैदा हो गया। केदार धाम से लेकर नीचे घाटी में फंसे 15 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों को सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और वाईएमएफ सहित थल और वायुसेना के साझा बचाव अभियान के तहत सुरक्षित निकाला जा सका। तीन यात्रियों के शव भी मलबे में बरामद हुए। केदारनाथ क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक और भूगर्भीय स्थिति ऐसी है कि वहां भूस्खलन, भूकम्प और बादल फटने जैसी प्राकृतिक घटनाओं के साथ चलने की कला सीखनी ही होगी। अगर हमने प्रकृति के प्रतिकूल जिद नहीं छो?ी तो भगवान केदारनाथ के कोप का बार-बार भाजना बनना ही होगा।

इसरो ने 2023 में देश के भूस्खलन संवेदनशील 147 जिलों का जोखिम मानचित्र तैयार किया था। इसमें सबसे ऊपर रुद्रप्रयाग जिले को रखा था, जहां 31 जुलाई को आई आपदा के कारण इन दिनों हजारों तीर्थयात्रियों की जानें संकट में फंसी रही। दूसरे नम्बर पर उत्तराखंड का ही टिहरी जिला अत्यंत जोखिम की श्रेणी में रखा गया था। वहां भी गत 26 एवं 27 जुलाई की रात को भूस्खलन से तिनगढ़ गांव तबाह हो गया। इसरो के जोखिम मानचित्र पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से लगे केरल के वायनाड सहित सारे 14 जिले शामिल किये गये थे।वर्ष 2013 की आपदा के बाद, शासन स्तर पर केदारनाथ में डॉप्लर राडार लगाने की बात कही गई थी, जिससे मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिल सके और इस तरह की मुश्किलों से निपटने के लिए पहले से इंतजाम किए जा सकें। लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केदारनाथ क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित नहीं हो सका। विशेषज्ञों का कहना है कि केदारनाथ में डॉप्लर राडार स्थापित होता तो बीते 31 जुलाई को पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए शासन, प्रशासन को इतनी मशक्कत नहीं करनी प?ती।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने केदार घाटी, जो कि सबसे संवेदनशील मुख्य केन्द्रीय भ्रंश (एमसीटी) के दायरे में आती है, तथा केदारनाथ धाम, जो स्वयं एक मलबे पर स्थित है, वहां भारी निर्माण की सख्त मनाही कर रखी है। वहां फिर भी सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के नाम पर बहुत भारी निर्माण कर दिया गया। यही नहीं, सन? 2013 में चोराबाढ़ी ग्लेशियर पर बादल फटने और ग्लेशियर झील के टूटने के कारणों की अनदेखी की गयी। दरअसल, योजनाकार ही नहीं बल्कि आपदा प्रबंधक भी जलतंत्र की अनदेखी करने की भूल कर रहे हैं। हिमालय पर ऊपर च?ते

समय बादल स्थाई हिमाच्छादित क्षेत्र में बारिश की जगह बर्फ बरसाते हैं। लेकिन 2013 में ऐसा नहीं हुआ जो कि जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत था। केदार घाटी बहुत तंग है और उसके अंत में 3,583 मीटर ऊंचा केदार पर्वत या केदार डोम है। जिसे अलकनन्दा घाटी की ओर से चले बादल पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहीं बरस जाते हैं। तंग घाटी होने के कारण बादलों का वेग अधिक होता है जिससे पहाड़ से टकराकर बादल फटने जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिये इस घाटी में निरन्तर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं।एक स्वैच्छिक संगठन की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने 2018 में केदारनाथ की बेहद सीमित धारण क्षमता को अनुभव करते हुए वहां प्रतिदिन 5000 से कम यात्रियों के जाने की सीमा तय की थी। लेकिन सरकार पर यात्रियों से ज्यादा हितधारकों और राजनीतिक दबावों के चलते इस साल सीमा को बढ़ाकर बदरीनाथ के लिये प्रतिदिन 20 हजार, केदारनाथ 18 हजार, गंगोत्री 11 हजार और यमुनोत्री के लिये 9 हजार यात्री कर दिया गया। इससे भी दबाव कम नहीं हुआ तो सरकार ने जून में सारी सीमाएं हटा दीं।

गौर करने वाली बात यह है कि पहले बदरीनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या केदारनाथ से बहुत अधिक रहती थी। बदरीनाथ के लिये सीधे वाहनों से जाया जाता है जबकि केदारनाथ के लिये लगभग 21 किमी की कठिन पैदल यात्रा भी है। लेकिन अब केदारनाथ में बदरीनाथ से अधिक भीड़ जा रही है। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व पूरे सीजन में केदारनाथ के यात्रियों की संख्या औसतन 1 लाख तक और बदरीनाथ जाने वालों की संख्या 9 लाख तक होती थी। पिछले साल केदारनाथ में 19,61,277 तक तीर्थयात्री पहुंच चुके थे। यात्रियों का यह सैलाब है जो कि केदारनाथ की धारण क्षमता से अत्यधिक होने से आपदा का एक कारण बन रहा है। यही नहीं, बहुत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाले इन धामों में वाहनों की बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है। अति संवेदनशील गोमुख में भी इस साल अब तक 6,309 यात्री पहुंच गये जिनमें ज्यादातर कांवड़िये ही थे। प्रकृति के साथ अगर ऐसा ही खिलवाड़ होता रहेगा तो मानवीय संकट को टाला नहीं जा सकेगा। बेशक आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास की अत्यन्त आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दें कि अपने ही नागरिकों को जान के लाले पड़ जायें। इन आपदाओं के लिए हर बार वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के सुझावों और चेतावनियों की अनदेखी को जिम्मेदार माना जा सकता है।

– साभार

भारत छोड़ो आंदोलन: एक विश्लेषण

■ एल.एस. हरदेनिया

9 अगस्त को गाँधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य से कहा था कि भारत छोड़ो। यह तारीख वर्ष 1942 की है। यद्यपि गाँधी जी ने उनसे भारत छोड़ने की कोई तारीख तय नहीं की थी परंतु उनसे यह अपेक्षा की थी कि वे शीघ्र भारत को आड़ाद कर दें। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि ब्रिटिश शासन ने लगभग स्वयं तय कर दी थी। 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित किया गया था। दो दिन की लंबी बहस के बाद यह तय हुआ था कि गाँधी ब्रिटिश वायसराय को एक पत्र लिखेंगे जिसमें उनसे कहा जायेगा कि वे भारत को आड़ाद करने का इरादा साफ कर दें। यह पत्र उन्होंने अपनी अंग्रेड़ शिष्या मीरा के हाथ भेजने का तय किया। परंतु वायसराय ने मीरा से मिलने का समय नहीं दिया और उलटे 9 अगस्त की प्रातः बंबई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने सदस्य थे प्रातःकाल से उनकी गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी। गाँधी जी कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य नहीं थे परंतु उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।

कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आड़ाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सरोजनी नायडू, आदि को गिरफ्तार करके बंबई की सबसे बड़ी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस ले जाया गया। वहाँ एक पेसेंजर गाड़ी खड़ी थी। इस गाड़ी में सभी को बैठा दिया गया और उसे पूणे की तरफ रवाना कर दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और रास्ते में जितने भी स्टेशन आये लोगों की भारी भीड़ गुस्से में खड़ी मिली। भीड़ के लोग अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गाँधी जिन्दाबाद, नेहरू जिन्दाबाद, पटेल जिन्दाबाद, मौलाना जिन्दाबाद आदि नारे लगा रहे थे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस लाठी और अश्रु गैस आदि का उपयोग कर रही थी। इसमें कई लोगों को चोंट लगी। नेहरू यह बात सहन नहीं कर सके और ट्रेन से उतरकर पुलिस से मुठभेड़ लेने लगे।यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कांग्रेस के भीतर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को कब कहा जाए, इस पर मतभेद था। उस समय द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था। इस महायुद्ध में एक तरफ ब्रिटेन और अन्य वो देश थे जहाँ प्रजातंत्र था और उनके विरोध में वे देश थे जिनके राज्यों में तानाशाही थी और जो संकुचित विचारधारा में विश्वास करते थे। इनमें सबसे प्रमुख था हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह था। जिसकी राजनीति का आधार यहूदियों के प्रति घृणा थी। उसने घोषित किया था कि वह दुनिया से यहूदियों का नामोनिशान मिटा देगा। दूसरे थे इटली के मुसोलिनी। इसके अतिरिक्त उन दोनों से सहयोग किया एशिया के राष्ट्र जापान ने। नेहरू, मौलाना आड़ाद आदि यह मत रखते थे कि ऐसे मौके पर हमको ब्रिटेन के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए और इसलिए फिलहाल अंग्रेजों को भारत छोड़ने को न कहा जाए।

यह सोच भी थी कि यदि जर्मनी, इटली और जापान द्वितीय महायुद्ध में विजयी हो जाते हैं तो वे सारी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। आड़ादी के बाद जब नेहरू जी बर्मा गये तो वहां के प्रधानमंत्री ने नेहरू से कहा कि यदि युद्ध में जापान विजयी हो जाता तो क्या वह हमें आजाद रहने देताड़गाँधी जी की राय थी कि इसी मौके पर अंग्रजों से आड़ादी छीनी जा सकती है। वे यह भी कहते थे कि यदि हमें आड़ाद कर दिया जायेगा तो हमारे देश का एक-एक बच्चा ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रों की मदद करेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए ब्रिटेन ने एक कमीशन भेजा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम के उनके एक बड़े नेता को उसका अध्यक्ष बनाया गया। क्रिप्स ने आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद हम भारत को आड़ाद कर देंगे। गाँधी जी को यह बात मंजूर नहीं थी और ब्रिटेन के इस आफर को उन्होंने कहा यह एक ऐसा चैक है जो दिवालिया होने वाले बैंक से हमें दिया जा रहा है। बापू का मतलब यह था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन दिवालिया हो जायेगा और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इस मुद्दे पर बहस होती रही और अंततः जैसा हमेशा होता था बापू की बात मान ली गई। परंतु फिर भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने की कोई तिथि नहीं दी गई। बंबई में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि ही बापू के दस्तखत से वायसराय को जानी थी जो उन तक नहीं पहुंच पाई। अंग्रेजों ने कोई अवसर नहीं छोड़ा और उन्हें यह लगा कि बापू और कांग्रेस शीघ्र ही आंदोलन छेड़ देंगे इसलिए उन्होंने सभी नेताओं को सारे देश में गिरफ्तार कर लिया और शायद कहने लगे कि न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी। पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई।सभी नेताओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिश साम्राज्य ने बापू और कांग्रेस को आंदोलन की रूप रेखा बनाने का मौका ही नहीं दिया। साधारणतः जब बापू कोई आंदोलन छेड़ते थे तो उस आंदोलन का संचालन करने के लिए जिम्मेदारियां बांट देते थे, परंतु यह आंदोलन किन लोगों के नेतृत्व में चलेगा यह तय नहीं हो पाया और पूरे देश में आग लग गई। शुरू के एक दो दिन तो कुछ नहीं हुआ परंतु बाद में सारे देश में तूफान आ गया और हिंसक घटनाएँ होने लगीं। बापू कभी किसी भी आंदोलन को हिंसक नहीं होने देते थे। पर इस बार स्थिति कुछ और ही थी। पूर्व में जब भी उनका छेड़ा हुआ आंदोलन हिंसक रूप लेता था तो वह उसे स्थगित कर देते थे। परंतु इस बार हिंसक होने के बावजूद बापू ने ऐसा नहीं किया। इससे अंग्रेजी शासकों में घबराहट हुई। फिर भी बापू ने इस आंदोलन को और ज्यादा हिंसक नहीं होने दिया।

कांग्रेस में एक और समूह था जो आंदोलन में तोड़-फोड़ और ऐसी घटनाओं के करने में पीछे नहीं रहता था जिससे सरकार को नुकसान पहुंचे। जैसे- सरकारी इमारतों में आग लगाना, रेल की पटरी उखाड़ फेंकना, सरकार को सहयोग नहीं देना, नदी के पुल तोड़ देना। इस समूह का नेतृत्व करने वालों में सबसे प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण। उनका साथ देने वालों में थे डा. राममनोहर लोहिया और श्रीमती अरूणा आसफ अली। अरूणा आसफ अली उन लोगों में से थीं जो भूमिगत हो गईं। उन्हें खोजकर गिरफ्तार करना बहुत कठिन काम हो गया। बाद में यह भी पता लगा कि उन्होंने कुछ दिन भोपाल में भी शरण ली थी। इनके साथ बड़ी संख्या में अनेक कांग्रेसी हो लिए। जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया था परंतु वे किसी तरह जेल से भाग निकले और इस तरह के आंदोलन को नेतृत्व देने में सबसे अगुवा रहे।यद्यपि अंग्रेजों के शासन के दौरान उन्हें तोड़-फोड़ करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी परंतु बाद के जीवन में वे अहिंसा के पुजारी हो गए और बापू के प्रमुख शिष्यों में हो गये। एक मौका ऐसा आया जब उन्होंने इन्दिरा गाँधी का तख्ता पलटने वाले आंदोलन की अगुवाई की। जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजों की दिक्कतों को बहुत बड़ा दिया था। एक और समूह था जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट कर रहे थे। प्रजातांत्रिक देशों पर हमला बोलने के साथ हिटलर ने अपने इस इरादे की भी घोषणा की थी कि वह दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश को भी नस्तेनाबूद कर देगा। यह देश था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सारी दुनिया के कम्युनिस्टों के लिए सोवियत संघ एक आदर्श था। उसकी रक्षा करना सभी कम्युनिस्ट अपना प्राथमिक उत्तरदायित्व समझते थे। चूंकि हिटलर प्रजातांत्रिक और कम्युनिस्ट राज्य को समाप्त करने पर आमादा था इसलिए विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बावजूद प्रजातांत्रिक देश और कम्युनिस्ट रूस एक दूसरे के घनिष्ठ सहयोगी बन गए। यदि कम्युनिस्ट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन में शामिल होते हैं तो इससे रूस की रक्षा में बाधा आयेगी। इसलिए भारतीय कम्युनिस्टों ने स्वयं को भारत छोड़ो आन्दोलन से अलग कर लिया।जब भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस के बंबई सम्मेलन में रखा गया तो कम्युनिस्टों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजो को भारत छोड़ने के लिए कहने का यह उचित समय नहीं है। बापू ने उनकी निंदा करने के स्थान पर उनकी प्रशंसा ही की। बापू ने कहा कि इतने बड़े जन-समूह की राय के विरोध में जो अपनी बात कहने का साहस रखते हैं, यदि इसी तरह की स्थिति आड़ाद भारत में आती है तो हमारे देश में प्रजातंत्र को कोई नष्ट नहीं कर पायेगा।

अंततः भारत छोड़ो आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका और उसे असफल क्रांति ही कहा जा सकता है। क्योंकि इतने जोरदार आंदोलन के बावजूद अंग्रेजों को हम भारत से भगा नहीं सके और उसके बाद भी पांच साल तक अर्थात 1947 तक अंग्रेज भारत पर शासन करते रहे। परंतु 1942 के आंदोलन से एक लाभ यह हुआ कि हमारे देश के आम आदमी में एक अद्भुत साहस ने जन्म लिया और यह बाद में भी हमारे देश में प्रजातंत्र बनाये रखने में सहायक सिद्ध हुआ। 1942 के आंदोलन की असफलता के बाद भी देश के लोग बापू पर श्रद्धा करते रहे और वे हमारे देश का नेतृत्व करते रहे।

– लेखक राष्ट्रीय सेक्युलर मंच के संयोजक हैं यह उनके विचार हैं।